श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल, राजस्थान का उद्‌बोधन

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण

दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 **समय दोपहर 01.00 बजे**

स्थान – जोधपुर

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविन्द बोवडे जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति श्री एन. बी. रामाना जी, माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण मिश्रा जी, माननीय न्यायाधिपति श्री नवीन सिन्हा जी, माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी जी, माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश माहेश्वरी जी, माननीय न्यायाधिपति श्री रविन्द्र भट्ट जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री इन्द्रजीत महान्ति जी, माननीय न्यायाधीशगण, उपस्थित अतिथिगण, भाइयो, बहनो, पत्रकार साथियों और छायाकार बन्धुओं।

जनता को समर्पित इस न्याय के मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर मैं अपने आपको धन्य महसूस कर रहा हूँ। इस नवनिर्मित भवन में अन्याय को पहचानने और अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज्ञान, साहस और संयम के माध्यम से पीड़ितों को लाभान्वित किया जायेगा।

यह शहर भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और बीएसएफ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान के लिए भी जाना जाता है। यहां अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान और अनुसंधान संगठन एम्स, आईआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ–साथ न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ज्यूडिशियल अकादमी भी स्थापित है।

जोधपुरी कोट, लोक उत्सवों से उल्लासित, शानदार मिठाइयों और पारंपरिक भोजन का शहर जोधपुर को राजस्थान की कानूनी राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त है।

जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी और न्यायमूर्ति ए.के. माथुर जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, यह सभी जोधपुर के मूल निवासी रहे हैं।

रियासतों का विलय होने के बाद 30 मार्च, 1949 को आधुनिक राजस्थान बना। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर की प्रमुख रियासतों में अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली के साथ अपने स्वयं के उच्च न्यायालय भी थे। श्री बी.आर. पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी और श्री एस.पी. सिन्हा की समिति ने 27 मार्च, 1949 को अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि स्वतंत्र भारत में राजस्थान के नए बने राज्य का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित होना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यादेश, 1949 ने मौजूदा अदालतों को समाप्त कर उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में किया गया था।

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ वर्तमान में एक प्राचीन इमारत में काम कर रही है, जिसका निर्माण 1935 में लेफ्टिनेंट कर्नल के शासनकाल के दौरान किया गया था। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए एक नई इमारत को मौजूदा परिसर में बढ़े हुए न्यायिक कार्यों की समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। भविष्य में समय पर न्याय देने और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में शीघ्र परीक्षण के अभिनव तरीकों को शामिल करने की आवश्यकता है।

राजस्थान की कानूनी राजधानी, जोधपुर में न्याय के इस नवनिर्मित मंदिर की आधारशिला 20 अप्रैल, 2007 को रखी गई थी। शानदार खंभों वाली इमारत की प्रभावशाली गोलाकार संरचना मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के मितौली गाँव में 11 वीं शताब्दी के चौसठ योगिनी मंदिर की याद दिलाती है।

कहा जाता है कि संसद भवन भी उसी मंदिर के बाद बनाया गया है। यह बाहरी रूप से केंद्र में गुंबद के शानदार दृश्य के साथ गोलाकार है, जो इमारत की सुंदरता को बढ़ाता है। केंद्र में 15,000 वर्ग फुट क्षेत्र के व्यास वाला शानदार गुंबद लोगों को आकर्षित करता है।

न्यायपालिका लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। शताब्दियों पहले महर्षि गौतम ने न्यायशास्त्र की रचना की थी। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इस परिभाषा के अनुसार प्रमाणों द्वारा पदार्थ का परीक्षण करना न्याय कहलाता है। भारत में प्राचीन काल से ही न्याय शास्त्र के अध्ययन–अध्यापन की सुदीर्घ परम्परा रही है। इसी परम्परा का निर्वहन करते हुए भारत के संप्रभु गणराज्य को न्याय दिलाने, सामान्य सुरक्षा प्रदान करने, व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के साथ–साथ मानव सम्मान सुनिश्चित करने का कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप हमारी स्वतंत्रता के लिए पंथ, लिंग, धर्म आदि के किसी भी भेदभाव के बिना सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक न्याय, राष्ट्र के लोगों की आशा और उम्मीदों को न्यायपालिका देखती है। लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास है।

संवैधानिक सीमा के भीतर समाज में सभी के लिए स्वतंत्रता और अवसर में समानता दिलाने का प्रयास न्यायपालिका ही करती है। थॉमस हार्डी ने कहा था कि " किसी चरित्र की सुंदरता या कुरूपता न केवल उसकी उपलब्धियों में बल्कि उसके उद्देश्यों और कार्यों में भी निहित होती है। '' आज से, न्याय के इस नये भवन में भविष्य के न्यायिक अभियानों को अपनी क्षमताओं के साथ शुरू करें। न्याय के इस मंदिर की अखंडता और पवित्रता को बनाने में सभी सहयोगी बने। न्याय की अवधारणा में निहित सद्भाव, शांति और समावेशी समाज के निर्माण के लिए न्याय को प्राथमिकता दी जाए। न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए समय पर कार्य पूरे किये जाये।

कानून सामाजिक हितों के लिए होता है। लोक अदालत, कानूनी मदद व जागरूकता कार्यक्रम, राजस्थान के उच्च न्यायालय की पहल को प्रोत्साहित करते हैं। लोगों में जागरूकता लाने और कानून प्रणाली के कामकाज को मजबूत करने के लिए न्याय व्यवस्था सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए।

मैं मुख्य न्यायाधीश श्री इन्द्रजीत मोहंती और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के साथ–साथ उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान के उच्च न्यायालय की पूरी कानूनी बिरादरी को बधाई देता हूं। साथ ही उन सभी न्यायिक अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर शहर में आने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार ज्ञापित करता हूँ।

धन्यवाद, जय हिन्द।